



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

No. 135]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2004/आषाढ 8, 1926
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2004/ASADHA 8, 1926

काणिक्य एवं उद्घोग मंशालय

(काणिक्य विभाग)

जांच शुरूआत: संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2004

विषय: इण्डोनेशिया और थाइलैण्ड के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित जिप्सम प्लास्टर बोर्ड के आयात के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 14/29/2003-डीजीएडी.—मेरो इण्डिया जिप्सम लिमिटेड, नई दिल्ली ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन)

अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें इण्डोनेशिया और थाइलैण्ड मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित जिप्सम प्लास्टर बोर्ड के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. विचाराधीन उत्पाद:- वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकारों और आकारों का जिप्सम प्लास्टर बोर्ड है। जिप्सम प्लास्टर बोर्ड का विनिर्माण और उसकी आपूर्ति सामान्यतः अलग-अलग आयामों और आकारों में की जाती है जिसकी मोटाई 6-16 मिमी, चौड़ाई 600-1250 मिमी और लम्बाई 1800-3200 मिमी होती है।

जिप्सम प्लास्टर बोर्ड मुख्यतः भवनों के आंतरिक भागों के विभाजनों और अस्थाई सीलिंग के रूप में किया जाता है। साज-सज्जा के अलावा यह अनिरोधी एवं पारिस्थितिक अनुकूल उत्पाद है।

जिप्सम प्लास्टर बोर्ड सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय शीर्ष 6809.11 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, आयात आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध वस्तु का आयात 6809 1900, 6809 900, 6811 9000 जैसे अन्य उपशीर्षों के अंतर्गत भी किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के द्वायर पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति:- यह याचिका मै 0 इण्डिया जिप्सम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है। इण्डिया जिप्सम लिमिटेड भारत में इस सामग्री का एकमात्र उत्पादक है।
3. शामिल देश/क्षेत्र:- वर्तमान जांच में शामिल देश/क्षेत्र इण्डोनेशिया और थाईलैण्ड हैं (जिन्हें आगे संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है)
4. समान वस्तुएं:- याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु इण्डोनेशिया और थाईलैण्ड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तुएं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश/क्षेत्र से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

5. पाटन और पाटन मार्जिन:-

- सामान्य मूल्य:- याचिकाकर्ता ने इण्डोनेशिया और थाईलैण्ड के मामले में सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

निर्यात कीमत:- याचिकाकर्ता ने आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है।

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि इण्डोनेशिया और थाईलैण्ड में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस कीमत से काफी अधिक है जिस कीमत पर इसका भारत को निर्यात किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि इण्डोनेशिया और थाईलैण्ड के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

6. क्षति एवं कारणात्मक संबंधः- घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक मापदंड जैसे कि उत्पादन, बिक्री, लाभ/हानि इत्यादि सामूहिक एवं संचयी रूप से यह संकेत देते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है । इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

7. पाटनरोधी जांच की शुरूआतः- उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथ उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।

8. जांच की अवधि:- वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि **जनवरी 2003- दिसंबर 2003 है ।**

9. सूचना प्रस्तुत करना:- संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत के आयातकों जो इस जांच के संबंध में ज्ञात हैं, को निर्धारित विधि और पद्धति से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है और उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि वे अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 को अवगत कराएं । अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार जांच से संबंधित अपने निवेदन निम्नानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित विधि और पद्धति में कर सकता है ।

10. समय सीमा:- वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच

जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।

11. चूँकि, पाटनरोधी जाँच एक समयबद्ध कार्यवाही है, तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार दी गई सीमा के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा किसी भी तरह से सूचना के अपूर्ण होने की स्थिति में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

12. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:- नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

13. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करती है अथवा महत्वपूर्ण ढंग से जाँच में बाधा डालती है अथवा सूचना किसी भी रूप में अधूरी होती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2004

Subject : Initiation of anti-dumping investigations concerning import of Gypsum Plaster Board originating in or exported from Indonesia and Thailand.

No. 14/29/2003-DGAD.— M/s India Gypsum Ltd., New Delhi, has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Gypsum Plaster Board originating in or exported from Indonesia and Thailand and has requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. Product Under Consideration: The product under consideration in the present case is Gypsum Plaster Board of all types and sizes. The Gypsum Plaster Board are generally manufactured and supplied in the different dimensions and sizes having thickness 6-16 mm, width 600-1250 mm and length 1800-3200 mm.

Gypsum Plaster Board is mainly used as partitions and false ceilings for interiors of buildings. Besides providing décor, it is a fireproof and eco-friendly product.

Gypsum Plaster Board is classified under Chapter Heading 6809.11 of the Customs Tariff Act, 1975. However, it may be noticed from the import statistics that the subject goods have also been imported under other sub-headings like 6809 1900, 6809 9000, 6811 9000. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

2. Domestic Industry Standing: The petition has been filed by M/s India Gypsum Ltd., New Delhi. India Gypsum Limited is the sole producer of this material in India.

3. Country(ies)/ Territory Involved: The countries/territory involved in the present investigations are Indonesia and Thailand (referred to as subject countries/territory hereinafter).

4. Like Article(s): The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from Indonesia and Thailand. Goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries/territory within the meaning of the Rules.

5. Dumping and Dumping Margin:

Normal Value: The petitioner has constructed the normal value in case of Indonesia and Thailand.

Export price: The petitioner has claimed export price based on the import figures.

Considering the normal value and export price the dumping margins are significantly higher than the de-minimis limit.

There is sufficient evidence that the normal values of the product under consideration in the Indonesia and Thailand are significantly higher than the prices at which it has been exported to India, indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by the exporters from Indonesia and Thailand.

6. Injury and Causal Link: The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, profit/loss etc. collectively and cumulatively, indicates that the domestic industry has suffered injury. There is sufficient *prima facie* evidence that the imports of the product under consideration have caused material injury to the domestic industry.

- 7. Initiation of Anti-Dumping Investigation:** In view of the foregoing paragraph, the Designated Authority initiates anti-dumping investigations to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries/territory.
- 8. Period of Investigation:** The period of investigation for the purpose of the present investigations is January, 2003 to December 2003.
- 9. Submission of Information:** The exporters in the subject countries/territory and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate of Anti-Dumping, Udyog Bhavan, New-Delhi –110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
- 10. Time Limit:** Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.
- 11. Anti-dumping investigations being a time bound exercise, the Designated Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the information is incomplete in any respect.**
- 12. Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
- 13. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.**

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority